(ग) क्या इन्दिरा नहर का प्रयोग राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों के औद्योगीकरण के लिए किया जायेगा और यदि हां, तो इस संबंध में कौन-कौन सी योजनायें हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम): (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस बात पर बल दिया गया है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए नये एककों की स्थापना करने के बजाय विद्यमान सुविधाओं का पुनर्गठन करके, उत्पादकता बढ़ाकर, तकनोलोजी का उत्थान करके तथा विद्यमान एककों का आधुनिकीकरण करके विद्यमान सुविधाओं का उपयोग अधिकाधिक किया जाए। राजस्थान में केन्द्रीय सरकार के अधीन महत्वपूर्ण योजनाओं की एक सूची अनुबंध के रूप में संलग्न है।

राजस्थान की सातवीं पंचवर्षीय योजना में बड़े तथा मझौले उद्योगों की स्थापना हेतु 66.07 करोड़ रुपये और ग्रामीण तथा लघु उद्योगों की स्थापना हेतु 46.05 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। किसी राज्य या उसके किसी विशेष जिले में उद्योगों का विकास करने का प्राथमिक दायित्व संबंधित राज्य सरकार का होता है। केन्द्र सरकार तो राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। औद्योगिक परियोजना के स्थापना-स्थल का निर्णय तकनीकी-आर्थिक बातों के आधार पर किया जाता है। तकनीकी-आर्थिक बातों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय परियोजनाओं की स्थापना हेतु औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। जो क्षेत्र पिछड़े क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं उन क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन देकर सरकार उद्योग के छितराव को भी बढ़ावा देती है। राजस्थान में चार विकास केन्द्रों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है जो पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को आकर्षित करेंगे।

(ग) इन्दिरा गांधी नहर कैनाल (स्टेज-II) की अनुमोदित परियोजना के अनुसार राजस्थान के जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर जिलों में पीने और औद्योगिक कार्यों के लिए 0.65 एम ए एफ (900 क्यूसेक्स) का प्रावधान है।

विवरण

सातवीं पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में औद्योगिक परियोजनाओं की सूची

1. हिन्दुस्तान जिंक लि० (विभिन्न परियोजनाएं)
2. हिन्दुस्तान कॉपर लि० (विभिन्न परियोजनाएं)
3. पाइराइट्स, फॉस्फेट एण्ड कैमिकल्स लि० (विभिन्न परियोजनाएं)
4. इन्सट्रूमेंटेशन लि० (कोटा)
5. हिन्दुस्तान साल्ट लि०
6. एच० एम० टी० लि० (विभिन्न परियोजनाएं)
7. आई. डी. पी. एल. संयुक्त उद्यम
8. भारी पानी संयंत्र, कोटा
9. कोटा में और सुविधाएं

Zero Industry Status for Districts of Uttar Pradesh

581. PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 15 districts of Uttar Pradesh were given zero status from the point of view of industrial development;

(b) whether it is also a fact that entrepreneurs there were offered subsidy till September 30, 1988;

(c) whether this offer of subsidy was suddenly withdrawn on September 22, 1988 exposing the entrepreneurs applying for such subsidy on investing money to serious situation; and

(d) if so, whether Government would examine the position and take remedial measures to ease the situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) to (d) 11 districts in Uttar Pradesh have been identified as No Industry Districts. With effect from 22.9.1988, non-manufacturing units have been made ineligible for Central Investment Subsidy. The Central Investment Subsidy Scheme stands extended upto 30.9.1988.

Setting up of Major and medium Industries in Orissa during Seventh Plan Period

582. SHRI JAGADISH JANI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have set up